Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

मार्च (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार **3**

- प्रधानमंत्री ने बिहार में विकास परियोजनाओं का अनावरण किया 3
- प्रधानमंत्री ने बिहार में परियोजनाओं का अनावरण किया 4
- बिहार में 'आयुष्मान भारत' कार्ड जारी 4
- बिहार में नई वंदे भारत एक्सप्रेस 6
- वर्ष 2070 तक बिहार का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पाँच गुना बढ़ जाएगा 6
- बेगुसराय: विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर 7
- नाबार्ड ने बिहार के लिये ऋण क्षमता का प्रोजेक्ट किया 9
- ONGC बिहार में कुआँ खोदेगी 9
- बिहार दिवस 2024 10
- न्यूयॉर्क में 'बिहार दिवस' पर प्रमुख भारतीय-अमेरिकियों को सम्मानित किया 11
- भारत रोज़गार रिपोर्ट 2024 13

नोट :

बिहार

प्रधानमंत्री ने बिहार में विकास परियोजनाओं का अनावरण किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद ज़िले में 21,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया।

मुख्य बिंदु:

- 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
- PM ने गंगा पर छह लेन वाले पुल की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण मौजूदा जेपी (जयप्रकाश नारायण) गंगा सेतु के समानांतर किया जाएगा। साथ ही, पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा और यह 'एक ज़िला, एक उत्पाद' परियोजना को बढ़ावा देगा।
- उन्होंने तीन रेलवे परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं, जिनमें पाटलिपुत्र-पहलेजा लाइन का दोहरीकरण और बँधुआ एवं पैमार के बीच 26 किलोमीटर लंबी नई लाइन शामिल है।
- पीएम ने नमामि गंगे योजना के तहत 2,190 करोड़ से अधिक की 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया।
  - इनमें पटना, सोनपुर, नौगछिया और छपरा के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल हैं।

एक ज़िला एक उत्पाद पहल

- ODOP देश के प्रत्येक ज़िले से एक उत्पाद को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करके ज़िला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक ज़िले की स्थानीय क्षमता, संसाधनों, कौशल और संस्कृति का लाभ उठाना तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाना है।
- ODOP की अवधारणा को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में विकसित की गई थी।
  - यह योजना राज्य के पारंपरिक उद्योगों और शिल्प, जैसे- चिकनकारी कढ़ाई, पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कालीन, चमड़े की वस्तुएँ आदि को पुनर्जीवित करने में सफल रही।
  - इससे प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने इस अवधारणा को अपनाया और इसे एक राष्ट्रीय पहल के रूप में लॉन्च किया।

नमामि गंगे कार्यक्रम

- नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग है (वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था; जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण-NGRBA का स्थान लिया)।

नोट :

प्रधानमंत्री ने बिहार में परियोजनाओं का अनावरण किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया।

मुख्य बिंदु:

- प्रधानमंत्री ने पश्चिम चंपारण के ज़िला मुख्यालय बेतिया में 'विकसित भारत-विकसित बिहार' नामक एक समारोह में परियोजनाओं का अनावरण किया।
- उन्होंने आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया:
  - रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ।
  - पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान एवं देवरिया में शहरी गैस वितरण परियोजना तथा सुगौली एवं लौरिया में अनाज आधारित इथेनॉल सुविधाएँ।
  - पटना में दीघा-सोनेपुर रेल-सह-सड़क पुल के समानांतर गंगा नदी पर छह-लेन केबल पुल का निर्माण और NH-19 बाईपास के बाकरपुर हाट-मानिकपुर खंड को चार लेन का बनाना।
  - 96 किमी लंबी गोरखपुर कैंट वाल्मिकी नगर रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण तथा बेतिया स्टेशन का पुनर्विकास।
- उन्होंने उद्घाटन किया:
  - राष्ट्रीय राजमार्ग-28A के पिपराकोठी-मोतिहारी-रक्सौल खंड को दो लेन का और NH-104 के शिवहर-सीतामढ़ी खंड को दो लेन का बनाया जाएगा।
  - 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुज़फ्फरपुर-मोतिहारी LPG पाइपलाइन जो राज्य और नेपाल में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुँच प्रदान करेगी।
  - मोतिहारी में इंडियन ऑयल का LPG बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल।
  - बापूधाम मोतिहारी से पिपराहां तक 62 किमी लंबी लाइन और नरकटियागंज-गौनाहा खंड का आमान परिवर्तन।
- उन्होंने नरकटियागंज-गौनाहा और रक्सौल-जोगबनी सेक्शन के लिये दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।

बिहार में 'आयुष्मान भारत' कार्ड जारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- केवल छह दिनों में (8 मार्च सुबह 11 बजे तक) 1.03 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किये गए।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल मिलता है और वे प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं।
- राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, छह दिवसीय अभियान में सबसे अधिक 5,99,609 आयुष्मान भारत कार्ड सीवान ज़िले में जारी किये गए, इसके बाद मुज़फ्फरपुर में 5,44,018, पटना में 5,00,292 और मधुबनी में 4,72,977 कार्ड जारी किये गए।
- जिन ज़िलों में विशेष अभियान में एक लाख से कम आयुष्मान भारत कार्ड जारी किये गए, वे हैं- मुंगेर (99,984), किशनगंज (76,861), शेखपुरा (58,132) और शिवहर (47,288)।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

- PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।

नोट :

- इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया, यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है।
- स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं व निदान की लागत शामिल है।
- लाभार्थी:
  - यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शेष (अप्रामाणित) SECC परिवारों की पहचान करने के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
- वित्तीयन:
  - इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के लिये 90:10 और विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।
- केंद्रक अभिकर:
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
  - राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

- इसे 10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था।
- इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को शामिल किया गया है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।
- पात्रता:
  - राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर।
  - अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।
- प्रावधान:
  - प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेंहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो।
  - हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
  - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
  - 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
  - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
  - ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

नोट :

बिहार में नई वंदे भारत एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ राज्य में कई रेलवे परियोजनाओं का अनावरण किया।

मुख्य बिंदु:

- ये अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम द्वारा अनावरण की गई 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में से एक थीं।
- दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें पटना-गोमती नगर और पटना-न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर संचालित की जाएंगी।
  - पटना-गोमती नगर वंदे भारत का पड़ाव वाराणसी और अयोध्या धाम के तीर्थ नगरों में होगा, जबकि तीसरी वंदे भारत, जिसे भी हरी झंडी दिखाई गई, रांची से वाराणसी के रास्ते में गया में रुकेगी।
- पीएम ने नरकटियागंज में वाशिंग पिट सह कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया।
- उन्होंने उद्घाटन किया:
  - ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू चिरैला पौथु-न्यू सोन नगर-न्यू दीन दयाल उपाध्याय (DDU) खंड।
  - गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, पटना और दरभंगा में जन औषधि दवा भंडार, आरा तथा मुजफ्फरपुर में गुड्स शेड एवं वाशिंग पिट लाइनें।
  - 'एक स्टेशन एक उत्पाद योजना' आउटलेट जो स्थानीय छोटे किसानों और कारीगरों को बढ़ावा देंगे।

बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) मुज़फ्फरपुर और मोतिहारी सर्कल में सबसे तेज़ 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर (SPM) की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु:

- मुज़फ्फरपुर और मोतिहारी दोनों सर्किलों में 10 लाख SPM 14 महीनों में स्थापित किये गए।
- NBPDCL ने मुज़फ्फरपुर शहरी-2 डिवीज़न के पहले ग्रामीण डिवीज़न को संतृप्त करने की उपलब्धि भी हासिल की।
- इसका अर्थ है कि मुज़फ्फरपुर शहरी-2 डिवीज़न के 100% घर SPM द्वारा शामिल किये गए हैं।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर

- ये आधुनिक ऊर्जा मीटर हैं जिनका उपयोग वास्तविक समय में विद्युत की खपत को रिकॉर्ड करने के लिये किया जाता है।
- चूँकि वे इंटरनेट से जुड़े हैं, उपयोगकर्त्ता और उपयोगिताएँ आसानी से विद्युत के उपयोग को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं तथा सटीक बिल प्राप्त कर सकते हैं।
- उनकी दूरस्थ मीटर रीडिंग क्षमताएँ मैन्युअल निरीक्षण की आवश्यकता को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, जिससे वे अत्यधिक कुशल और सुविधाजनक बन जाते हैं।

वर्ष 2070 तक बिहार का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पाँच गुना बढ़ जाएगा

चर्चा में क्यों ?

'क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो-कार्बन डेवलपमेंट पाथवे' रिपोर्ट के अनुसार, बिहार का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है, जब भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्य बिंदु:

- यह निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में थे।
  - बिहार सरकार ने फरवरी 2021 में जलवायु लचीले और कम कार्बन विकास मार्ग के लिये रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

नोट :

- मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है कि:
  - वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उत्सर्जन में बिहार का योगदान भारत के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3.3% है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी (8.8%) से कम है, जबकि वर्ष 2005 और वर्ष 2013 के बीच यह दोगुना हो गया था।
  - वर्ष 2018 में कुल 69% योगदान के साथ ऊर्जा क्षेत्र ग्रीनहाउस गैसों का उच्चतम उत्सर्जक था, इसके बाद कृषि, वन और अन्य भूमि उपयोग 24%, अपशिष्ट प्रबंधन 5% एवं औद्योगिक प्रसंस्करण व उत्पाद उपयोग 2% था।
  - यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, तो वर्ष 2020 और वर्ष 2070 के बीच राज्य का उत्सर्जन 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है।
  - ऊर्जा क्षेत्र उच्चतम उत्सर्जक बना रहेगा, जिसका कुल उत्सर्जन में 93% योगदान होने का अनुमान है। इसके बाद निर्माण (6%), परिवहन (5%) और उद्योग (5%) का स्थान आता है।
  - उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रभुत्व विद्युत उत्पादन के लिये कोयले पर निरंतर निर्भरता के कारण है।
- चूँकि अधिकांश उत्सर्जन विद्युत क्षेत्र से होता है, इसलिये बिहार को भारत के शुद्ध शून्य वर्ष 2070 लक्ष्य के अनुरूप रहने के लिये वर्ष 2030 के बाद नए थर्मल पावर प्लांट खोलने से बचना होगा।
- इसलिये, राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों के साथ दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा विद्युत खरीद समझौते को सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, राज्य को छत पर सौर पैनल, फ्लोटिंग सोलर, कृषि-फोटोवोल्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य विकेंद्रीकृत रूपों जैसे विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार करने की आवश्यकता होगी।
- साथ ही, उद्योग, परिवहन और रियल एस्टेट के अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों को विद्युतीकृत करने की आवश्यकता होगी ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से उनसे होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)

- यह 5 जून 1972 को स्थापित एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
- यह वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक वकील के रूप में कार्य करता है।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन:

- इसे कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा।
- बल्कि, यह एक ऐसा देश है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है।
- 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य तक यानी वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य बनने का दावा किया है।
- भारत ने COP-26 शिखर सम्मेलन के सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा किया है।

बेगुसराय: विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर

चर्चा में क्यों ?

स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार, बिहार का बेगुसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया है।

मुख्य बिंदु:

- यह रिपोर्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों के बीच वायु प्रदूषण के स्तर में तीसरे स्थान पर भारत की रैंकिंग को रेखांकित करती है।
  - यह वर्ष 2022 से बदलाव का प्रतीक है जब भारत वायु प्रदूषण के मामले में विश्व स्तर पर आठवें स्थान पर था।
- 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत PM2.5 सांद्रता के साथ, बेगुसराय ने अन्य सभी महानगरीय क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है।
- दिल्ली को एक बार फिर सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इसका PM2.5 स्तर भी वर्ष 2023 में 89.1 से घटकर 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है।
  - दिल्ली ने वर्ष 2018 से लगातार चौथे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी का खिताब बरकरार रखा है।

नोट :

- यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि:
  - लगभग 1.36 अरब लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के दिशा-निर्देश से अधिक PM 2.5 स्तर के संपर्क में हैं।
- 1.33 बिलियन व्यक्ति, जो कि भारतीय आबादी के 96% के बराबर है, WHO मानक से सात गुना अधिक PM2.5 स्तर से जूझ रहे हैं।
- इस रिपोर्ट के लिये डेटा विश्व में वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों और सेंसर के एक व्यापक नेटवर्क से संकलित किया गया था, जिसमें विभिन्न संस्थान, संगठन तथा नागरिक वैज्ञानिक शामिल थे।
  - वर्ष 2023 की रिपोर्ट ने 134 देशों में 7,812 स्थानों को शामिल करने के लिये अपने कवरेज़ का विस्तार किया है, जबकि वर्ष 2022 में 131 देशों में 7,323 स्थानों को शामिल किया गया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार:
  - वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक मुद्दा बना हुआ है, जो विश्व में नौ में से लगभग एक मृत्यु का कारण बनता है।
  - WHO का अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष सात मिलियन व्यक्तियों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, जिससे व्यक्ति अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी जैसी विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों से प्रभावित होते हैं।
  - PM2.5 प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है और मधुमेह जैसी मौजूदा बीमारियाँ बढ़ सकती हैं।

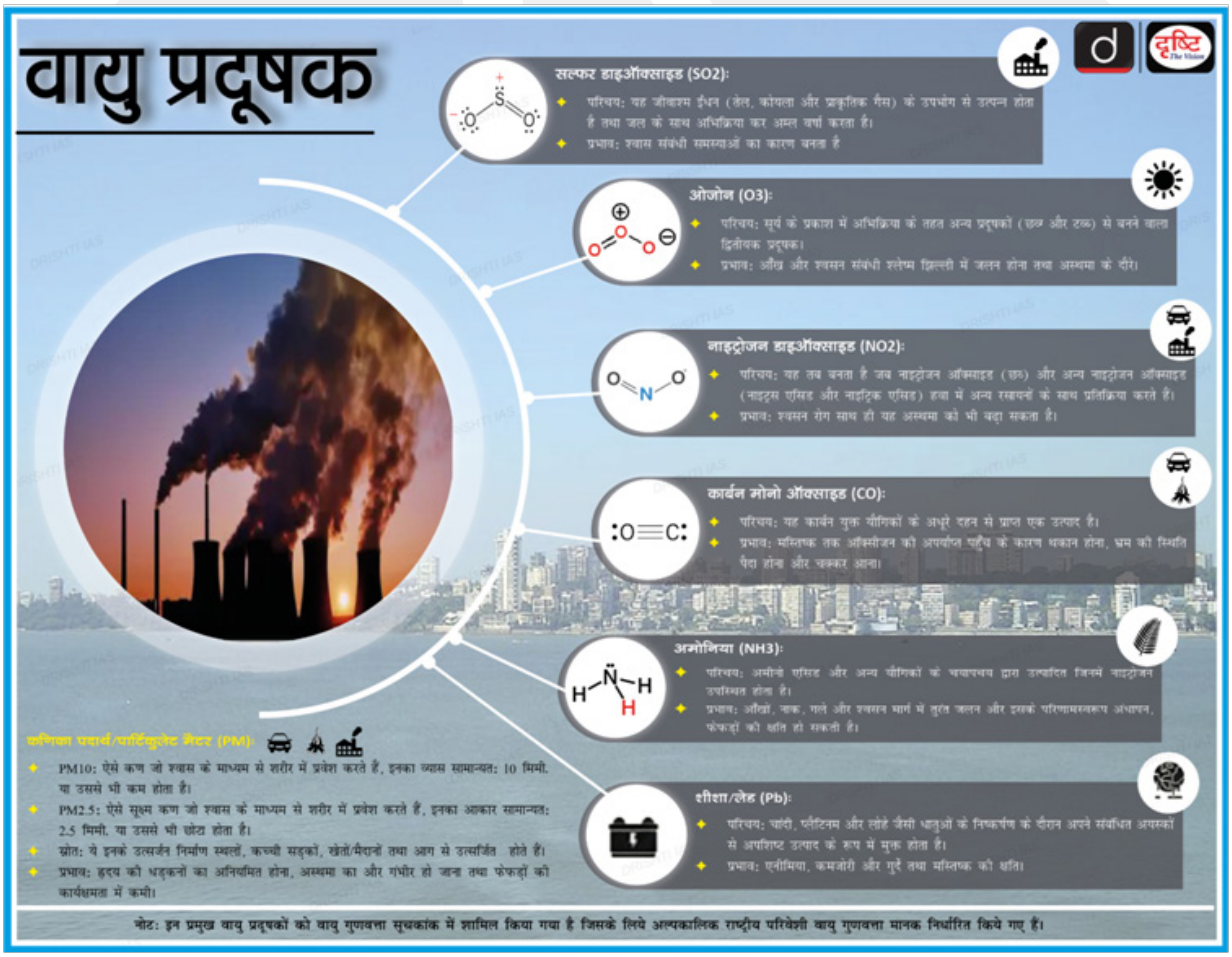

नोट :

नाबार्ड ने बिहार के लिये ऋण क्षमता का प्रोजेक्ट किया

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिये 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है।

मुख्य बिंदु:

- यह अनुमान भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र-आधारित दिशा-निर्देशों, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों तथा टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिये नीतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
- नाबार्ड के क्रेडिट सेमिनार में विकास आयुक्त द्वारा बिहार के लिये स्टेट फोकस पेपर 2024-25, राज्य के सभी 38 ज़िलों के लिये मूल्यांकन किये गए ऋण प्रवाह का एक संकलन का अनावरण किया गया।
  - वर्ष 2024-25 के लिये प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कुल ऋण प्रवाह 2,43,093 करोड़ रुपए अनुमानित है।
- बिहार में कृषि के अंतर्गत प्रत्येक उप-क्षेत्र के लिये विशिष्ट योजना के माध्यम से ऋण सघनीकरण की आवश्यकता है।
  - राज्य में आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन में ऋण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

- यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिये वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है।
- इसका मुख्यालय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है।
- यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों और ऐसे किसी भी अन्य गाँव या ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह वर्ष 1982 में संसदीय अधिनियम-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।
- रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था लेकिन वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहाँ गवर्नर बैठते हैं और जहाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं।
- हालाँकि मूल रूप से निजी स्वामित्व में, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से, रिज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

ONGC बिहार में कुआँ खोदेगी

चर्चा में क्यों ?

तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने तेल एवं गैस के लिये बिहार में एक कुआँ खोदने की योजना बनाई है।

- इस व्यावसायिक खोज के चलते बिहार राज्य भारत के तेल मानचित्र पर आ जाएगा और इससे बिहार से उत्तर प्रदेश तथा पंजाब तक फैले पूरे गंगा बेसिन में खोज का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्य बिंदु:

- कंपनी ने समस्तीपुर में अपने ब्लॉक हेतु 300 वर्ग किमी. के लिये 3D भूकंपीय डेटा हासिल कर लिया है और दो खोजपूर्ण कुओं को ड्रिल करने के लिये तैयार है।
  - पहली ड्रिलिंग वर्ष 2024 में की जाएगी।
  - इसके अलावा, तेल और गैस उत्पादक ने उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा बेसिन के एक अन्य ब्लॉक में एक खोजपूर्ण कुआँ खोदने की भी योजना बनाई है।

नोट :

- पहले कुएँ की ड्रिलिंग का डेटा दूसरे कुएँ की ड्रिलिंग सहित बाकी अन्वेषण ब्लॉक के लिये कंपनी की योजनाओं को निर्देशित करने में सहायता करेगा।
  - समस्तीपुर और बलिया में दोनों ब्लॉक कुछ वर्ष पहले चौथे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) दौर में प्राप्त किये गए थे।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम(ONGC)

- यह भारत सरकार का एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी तथा यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है।
- यह भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 70% योगदान देती है।

गंगा बेसिन

- गंगा की जलधारा जिसे 'भागीरथी' कहा जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर से पोषित होती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है।
- हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों की ओर आती है।
- गंगा में हिमालय से कई सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी।

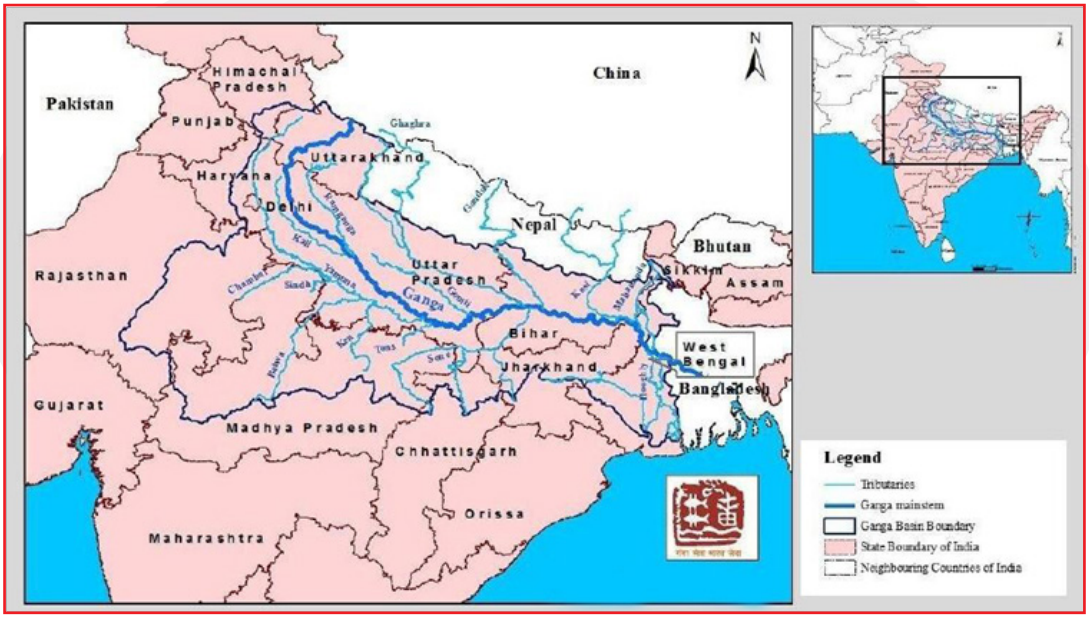

बिहार दिवस 2024

चर्चा में क्यों ?

बिहार डे या बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। यह पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के तहत कार्यालय, संगठन, बैंक तथा शैक्षणिक संस्थान बंद हैं।

मुख्य बिंदु:

- बिहार दिवस 2024, राज्य की स्थापना के 111 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, जिससे बिहार के लोगों के लिये अपने इतिहास पर विचार करना और अपनी पहचान का जश्न मनाना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है।
  - बिहार सरकार ने पूरे दिन को मनाने के लिये बहुसांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक शृंखला का समन्वय किया है।
  - यह उत्सव बिहार राज्य में लोगों के गौरव को बहाल करने के इरादे से आयोजित किया गया था।

नोट :

- बिहार दिवस बंगाल प्रेसीडेंसी से राज्य के विकास का प्रतीक है। इस राज्य का गठन 22 मार्च, 1912 को हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत का विभाजन किया था।
  - बिहार दिवस का जश्न उल्लास और उत्साह से मनाया जाता है। यह इस तथ्य के कारण है कि यह एक अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत वाले एक विशेष राज्य के रूप में उनके जीवन के तरीके की नींव को दर्शाता है।
  - यह दिन बिहार के लोगों को अपने इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और विरासत को दिखाने का मौका भी देता है।
- भारत के अलावा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, ब्रिटेन (स्कॉटलैंड), ऑस्ट्रेलिया, त्रिनिदाद व टोबैगो और मॉरीशस सहित देशों में मनाया जाता है।

न्यूयॉर्क में 'बिहार दिवस' पर प्रमुख भारतीय-अमेरिकियों को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार से आने वाले भारतीय-अमेरिकी प्रवासी के चार प्रमुख सदस्यों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिये 'बिहार दिवस' के अवसर पर सम्मानित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- होल्टेक इंटरनेशनल के संस्थापक और CEO डॉ. क्रिस सिंह, विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी अमित चौधरी, PRAN मेडिकल ग्रुप के संस्थापक डॉ. दिनेश रंजन और न्यूट्रीवेट फार्मकेयर के निदेशक अभिनव अतुल को सम्मानित किया गया।

नोट :

- बिहार फाउंडेशन यूएसए, ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (BJANA) की साझेदारी में न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें 'बिहार विश्व गौरव सम्मान' से सम्मानित किया गया।
- इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेश भी शामिल थे तथा इसमें बिहार और क्षेत्र के कई प्रवासी सदस्यों ने भाग लिया।
  - इसमें राज्य के विकास, पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, प्रसिद्ध मधुबनी कला और लोकप्रिय पाक व्यंजनों पर प्रकाश डाला गया।

बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (BJANA)

- इसकी स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के लोगों को एक साझा मंच पर लाने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में त्रि-राज्य क्षेत्र (न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एवं कनेक्टिकट) में बिहार और झारखंड के लोगों के बीच सामाजिक तथा सांस्कृतिक बंधन को सुविधाजनक बनाने के लिये की गई थी।

केंद्र सरकार ने 13 महत्त्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द कर दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बोलीदाताओं से खराब प्रतिक्रिया के बाद केंद्र ने महत्त्वपूर्ण खनिज बोलियों के पहले दौर में प्रस्तावित 20 ब्लॉकों में से 13 की नीलामी रद्द कर दी है।

मुख्य बिंदु:

- इन 13 महत्त्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों को, जिन्हें खराब प्रतिक्रिया मिली, उनमें ग्लौकोनाइट, निकल, क्रोमियम और प्लैटिनम समूह तत्त्व (PGE), पोटाश आदि शामिल हैं। वे बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में फैले हुए हैं।
- PGE- प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, रूथेनियम, इरिडियम और ऑस्मियम ऐसी धातुएँ हैं जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं तथा प्रकृति में एक साथ पाए जाते हैं।
- इससे पहले सरकार ने जून 2023 में देश के लिये महत्त्वपूर्ण माने जाने वाले 30 खनिजों की सूची जारी की थी। इनमें एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, ताँबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हेफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नाइओबियम, निकल, प्लैटिनम समूह तत्त्व (PGE), फॉस्फोरस और पोटाश शामिल हैं।
- रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम जैसे दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व (REE) भी इस सूची में मौजूद थे।

महत्त्वपूर्ण खनिज:

- महत्त्वपूर्ण खनिज ऐसे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं।
- इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता से आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- महत्त्वपूर्ण खनिजों की घोषणा:
  - यह एक गतिशील प्रक्रिया है और यह समय के साथ नई प्रौद्योगिकियों, बाज़ार की गतिशीलता एवं भू-राजनीतिक विचारों के उभार के साथ विकसित हो सकती है।
  - विभिन्न देशों के पास अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्त्वपूर्ण खनिजों की अपनी विशिष्ट सूची हो सकती है।
  - खान मंत्रालय के तहत विशेषज्ञ समिति ने भारत के लिये 30 महत्त्वपूर्ण खनिजों के एक समूह की पहचान की है।

नोट :

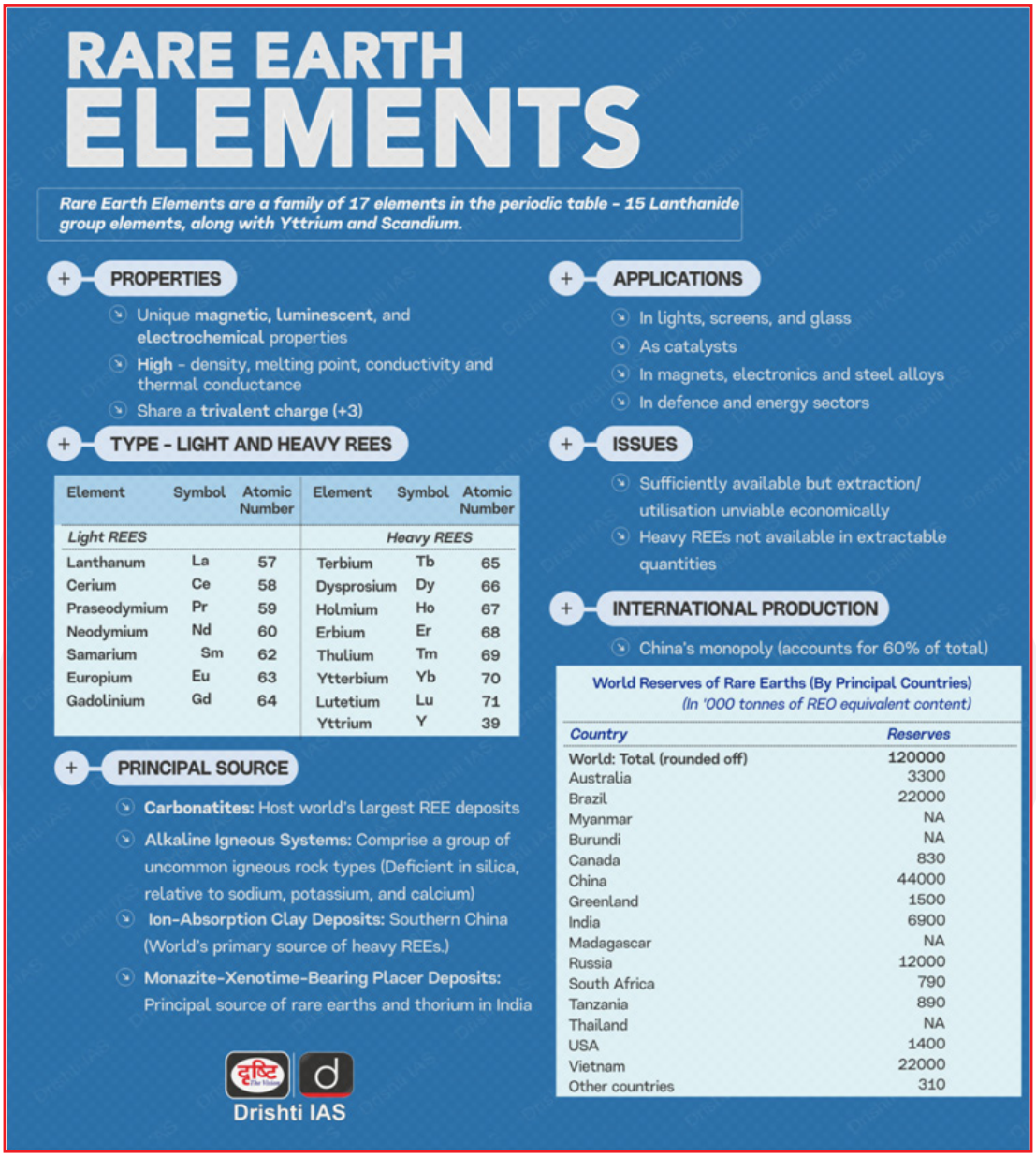

भारत रोज़गार रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों ?

मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी भारत रोज़गार रिपोर्ट 2024 के अनुसार, वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2021-22 के बीच राज्यों के 'रोज़गार स्थिति सूचकांक' में सुधार हुआ है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2004-05 और वर्ष 2021-22 के बीच "रोज़गार स्थिति सूचकांक" में सुधार हुआ है, लेकिन बिहार, ओडिशा, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य इस अवधि में सबसे निचले स्थान पर रहे हैं।

नोट :

- जबकि कुछ अन्य राज्य दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और गुजरात शीर्ष पर रहे हैं।

- यह सूचकांक सात श्रम बाज़ार परिणाम संकेतकों पर आधारित है:
  - नियमित औपचारिक कार्य में नियोजित श्रमिकों का प्रतिशत;
  - आकस्मिक मज़दूरों का प्रतिशत;
  - गरीबी रेखा से नीचे स्व-रोज़गार श्रमिकों का प्रतिशत;
  - कार्य भागीदारी दर;
  - आकस्मिक मज़दूरों की औसत मासिक कमाई;
  - माध्यमिक और उच्च-शिक्षित युवाओं की बेरोज़गारी दर;
  - रोज़गार और शिक्षा या प्रशिक्षण से बाहर युवा।

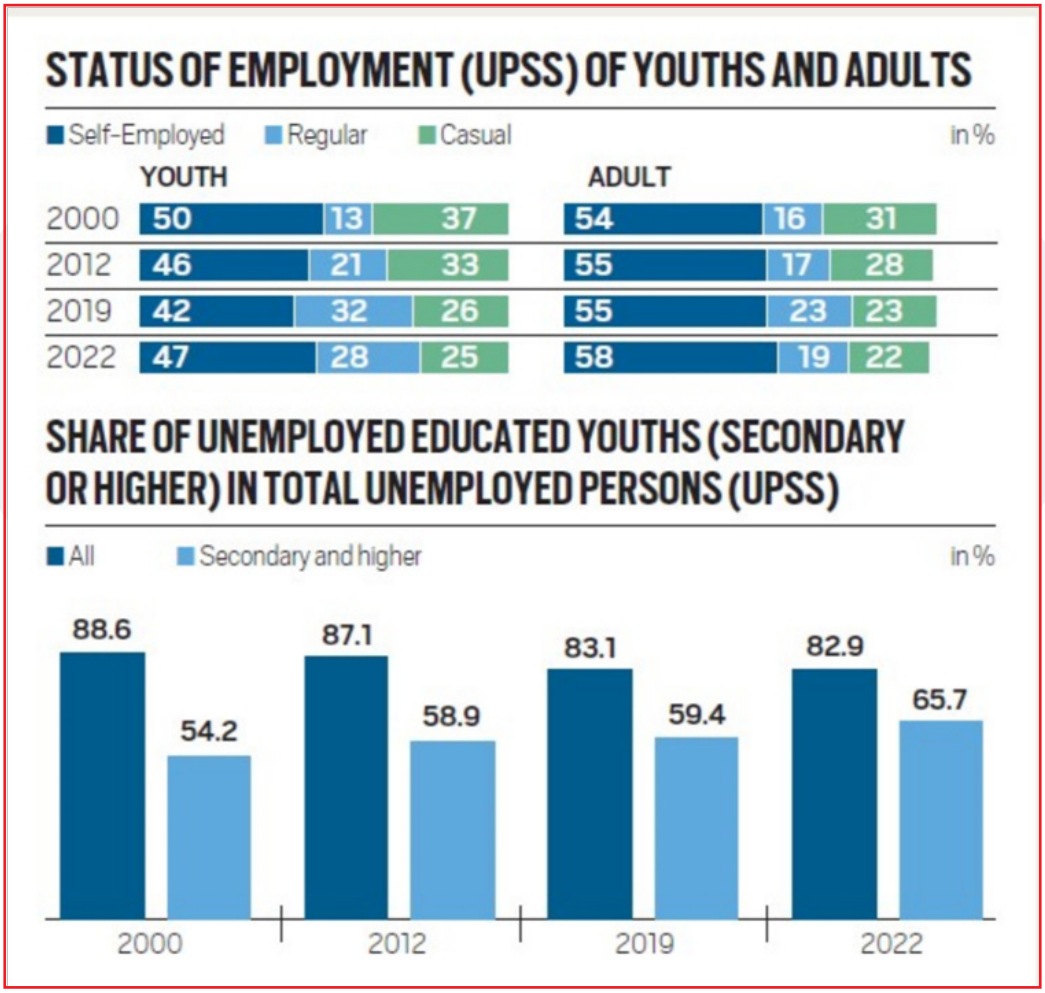

- रिपोर्ट में रोज़गार की खराब स्थितियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है: गैर-कृषि रोज़गार की ओर धीमी गति से बदलाव उलट गया है; स्व-रोज़गार और अवैतनिक पारिवारिक कार्यों में वृद्धि के लिये बड़े पैमाने पर महिलाएँ ज़िम्मेदार हैं; युवाओं का रोज़गार वयस्कों के रोज़गार की तुलना में खराब गुणवत्ता का है; मज़दूरी तथा कमाई स्थिर है या घट रही है।
- रोज़गार गुणवत्ता: लगभग 82% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है और लगभग 90% अनौपचारिक रूप से कार्यरत है। स्व-रोज़गार और अवैतनिक पारिवारिक कार्य में विशेषकर महिलाओं के लिये वृद्धि हुई है।

नोट :

- महिलाओं की भागीदारी: भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) दुनिया में सबसे कम है। वर्ष 2000 और वर्ष 2019 के बीच महिला LFPR में 14.4% अंक (पुरुषों के लिये 8.1% अंक की तुलना में) की गिरावट आई।
  - इसके बाद प्रवृत्ति उलट गई, वर्ष 2019 और वर्ष 2022 के बीच महिला LFPR में 8.3% अंक (पुरुष LFPR के लिये 1.7% अंक की तुलना में) की वृद्धि हुई।
- संरचनात्मक परिवर्तन: कुल रोज़गार में कृषि की हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 60% से गिरकर वर्ष 2019 में लगभग 42% हो गई। यह बदलाव बड़े पैमाने पर निर्माण और सेवाओं द्वारा अवशोषित किया गया था, कुल रोज़गार में हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 23% से बढ़कर वर्ष 2019 में 32% हो गई
- युवा रोज़गार: युवा रोज़गार में वृद्धि हुई है, लेकिन काम की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर योग्य युवा श्रमिकों के लिये। वर्ष 2022 में कुल बेरोज़गार आबादी में बेरोज़गार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी।

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि The Vision

नोट :